SHRI CHINTA MOHAN: About essential drugs, we are watching the situation...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केन्द्र

*406. **श्री अजीत जोगी :**
श्री बी० के० हरिप्रसाद :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अभी तक स्थापित किये गये औद्योगिक विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में खंड स्तर पर औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) देश में आदिवासी क्षेत्रों में और अन्य अल्प विकसित जिलों में, जहां कोई उद्योग नहीं है, स्थापित किये गये औद्योगिक विकास केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) विकास केन्द्र योजना के अधीन मध्य प्रदेश को 6 विकास केंद्र आवंटित किए गए हैं, इन सभी केन्द्रों हेतु स्थान का चयन कर लिया गया है और उसकी घोषणा भी कर दी गई है । इनमें से भिंड, धार, दुर्ग, गुना, रायपुर और रायसेन जिलों में से प्रत्येक जिले में एक एक केन्द्र है । इन क्षेत्रों में धार, दुर्ग तथा रायपुर ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदिवासियों का संकेन्द्रण है।

(ग) चुने गए तथा घोषित किए गये 63 विकास केन्द्रों में से 50 क्षेत्र केन्द्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्र हैं।

पंजाब में उद्योगों को आर्थिक राज सहायता

*407. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पंजाब में उद्योगों को केन्द्र सरकार द्वारा कोई आर्थिक राज-सहायता नहीं दी गई है ; यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) उस राज्य के उद्योगों को अन्तिम बार राजसहायता किस वर्ष प्रदान की गई थी और उस राजसहायता की राशि कितनी थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 30 सितम्बर, 1988 से बन्द कर दी गयी थी । यह योजना राज्य सरकारों के जरिए चलायी गयी थी और केन्द्र सरकार ने राज्यों को केवल राजसहायता की राशि की प्रतपूर्ति की थी । इस योजना के चालू रहने के दौरान पंजाब सरकार द्वारा वितरित की गई राजसहायता की राशि के लिए वर्ष 1988–89 से 1990–91 के दौरान राज्य सरकार को 2.9 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी ।

Export of Coir products

*408. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that MRP and floor price for the export of Coir products, hamper free trade as contemplated in the new industrial policy; and